The Lok Sabha reassembled after Lunch at Thirty Minutes Past Fourteen of the Clock.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS : (SHRI Y. B. CHAVAN) : I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967,

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.".

श्री मधु लिमये (मुंगेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का इसलिये विरोध करना चाहता हूँ कि इस बिल से पता चलता है कि इनका जो कानून मंत्रालय है, या बिल बनाने वाले जो लोग हैं वह कितने निकम्मे और अयोग्य हैं। क्योंकि जब बिल बनाते हैं तब संविधान की सारी धाराओं के बारे में सोचते नहीं हैं। स्वयं इन्होंने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स में कबूल किया है कि इनके विधेयक की कुछ धाराओं के बारे में संदेह है कि यह संविधान के अनुकूल है या नहीं है। तो सबसे पहले मेरा आक्षेप यह है कि इस तरह बार-बार संशोधन करने की जो जरूरत पड़ती है उसका साफ मतलब है कि विधेयक बनाते समय इनका कानून मंत्रालय या इन के कानूनी सलाहाकार इनको ठीक सलाह नहीं देते।

SHRI K. NARAYAN RAO (Bobbili) : On a point of order. Under what rule is he raising the point of order ?

श्री मधु लिमये : अगर आपको मालूम नहीं तो आप बैठ जाइये। मैंने इजाजत ली है नियम 72 में...

SHRI K. NARAYANA RAO : Shri Madhu Limaye has raised an objection against the introduction of the Bill. I am raising a point of order under rule 72 itself. If a Bill is opposed, the scope of the discussion at this stage will have to be confined to a mere statement of facts, but I find that he is going into the merits of so many things...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has mentioned that he is raising a constitutional aspect.

SHRI K. NARAYANA RAO : It is not a question of constitutional aspect. He has no right to be permitted to go into the other facts.

MR. DEPUTY-SPEAKER : So far as the procedural aspect is concerned, he is within his rights, and he has written to the Chair already.

The hon. Member may kindly see rule 72 which reads thus :

> "Provided that were a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon.".

The hon. Member has now got to prove it. He has just begun, and let us see what he has got to say.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : किस रूल के अन्डर माननीय सदस्य सदन का समय ले रहे हैं ? क्या कहना चाहते हैं यह ?

श्री रवि राय (पुरी) : यह रूल जानते नहीं हैं उपाध्यक्ष महोदय, आ कर के खामखवाह बात करते हैं।

श्री मधु लिमये : आप फैसला करने वाले कौन हैं। मैं स्लिप शाड ड्राफ्टिंग की बात कर रहा हूं।

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH (Parbhani) : On a point of order. The hon. Member has raised an objection on the ground that the officials of the Law Ministry had gone to a long sleep, Can this be raised an objection to the introduction on the ground of legislative competence ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Does the hon. Member want to suggest that this

*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 14-3-69.

House should not look to the drafting of the legislation ? That is the preliminary objection raised by Shri Madhu Limaye. That is perfectly valid.

श्री मधु लिमये : मेरा पहला मुद्दा यह था कि इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी ? क्योंकि विधेयक बनाने वाले जो लोग हैं, कानूनी सलाहकार यह स्लिप शाड ड्राफ्टिंग करते हैं वरना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती ।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि जब स्वयं मंत्री महोदय हमेशा यहां कहते हैं, जब मांग की जाती है कुछ लोगों के द्वारा कि शिव सेना पर, लच्छित सेना पर या आर० एस० एस० या मार्किसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी पर पाबन्दी लगाओ तो मंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि संस्थाओं पर पाबन्दी लगा कर काम नहीं चलेगा। विचारों में संघर्ष चलना चाहिये । मैं भी उनकी राय से मुत्तफिक हूँ । लेकिन मेरा यह सवाल है कि जब ऐसी स्थिति है तो कश्मीर के अन्दर जो संस्थायें हैं उन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह बिल आप आज काश्मीर राज्य में क्यों लागू करने जा रहे हैं तो इस का मैं विरोध करना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा कहना यह है कि काश्मीर में आज शहरी आजादियों पर आक्रमण हो रहा है । ऐसी हालत में यह नया काला कानून कश्मीर राज्य के लिये लागू करना मैं समझता हूं बिल्कुल अनुचित है ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या उनको इस बात को ले कर परेशानी नहीं है कि जब वे बम्बई के मुख्य मंत्री थे तब एक उदार नीति चलाने वाले और सौम्य शासक के नाते उन्होंने कुछ नाम कमाया था । लेकिन इधर दो सालों से मैं देख रहा हूँ कि वह लौह पुरुष बनने की कामना में अपने उस नाम को बदनाम कर रहे हैं । तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वह वापस लेलें और पूरा अनलाफुल ऐक्टीविटीज ऐक्ट जो है उसको वापस लेने वाला या रिपील करने वाला अमेंडमेंट ले आयें तब हम उसका स्वागत करेंगे और फिर उनका नाम फिर रौशन हो जायगा ।

SHRI RANDHIR SINGH : He has only brought in extraneous matter.

SHRI K. NARAYANA RAO : What he has raised falls outside the purview of this rule.

SHRI RANDHIR SINGH : He has criminally wasted two minutes of the House.

SHRI MADHU LIMAYE : No, no.

SHRI Y. B. CHAVAN : I was just waiting to hear some valid argument from him supporting his opposition to the introduction of the Bill.....

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has not referred to any constitutional aspect.

SHRI Y. B. CHAVAN : He has not raised any constitutional objection, but he has gone into the merits of the Bill.

As far as the principle of the Bill is concerned, the House has already accepted it. The only point that arises is this. At the time when we had this Bill passed, we were advised that it would be applicable to Jammu and Kashmir also. I must admit one thing which Shri Madhu Limaye has said, namely that the Law Ministry did not anticipate this difficulty at that time. But human efforts are always imperfect. As long as nobody stands to conceal the imperfections, there should be no objection. We have come forward before the House openly pleading that we did not see this legal difficulty then, and now we are advised legally that in order to remedy this position it is much better that the Act is amended again.

We can consider the merits of the Bill at the time of the consideration of the Bill. Now, I move that leave be granted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.".

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sir, I introduce the Bill.